BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर: औद्योगिक विकास का आधार

07 नवंबर, 2026

भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग अपने विनिर्माण आधार, निवेश क्षमता और अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव का विस्तार कर रहा है। समर्पित औद्योगिक पार्कों और इन्फ्रास्ट्रक्चर का उद्देश्य उत्पादन क्षमता में सुधार करना और निवेश को आकर्षित करना है। अनुसंधान वित्तपोषण, विशेष संस्थान और कौशल विकास उन्नत अनुप्रयोगों के लिए विशेषज्ञता का निर्माण कर रहे हैं। गुणवत्ता मानक और कार्यस्थल सुरक्षा उपाय जिम्मेदार औद्योगिक प्रणालियों को मजबूत करते हैं। साथ में, ये प्रयास इस क्षेत्र को अधिक मूल्यवर्धन, तकनीकी क्षमता और वैश्विक रासायनिक बाजारों में एक मजबूत भूमिका निभाने के लिए तैयार करते हैं।

रणनीतिक महत्व का उद्योग

भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग विनिर्माण, कृषि और औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके उत्पाद फार्मास्यूटिकल, कपड़ा, निर्माण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता वस्तुओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। भारत दुनिया में **रसायनों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक** और एशिया में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्तमान में इस क्षेत्र का मूल्य लगभग 220 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2040 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

भारत विशेष रासायनिक क्षेत्रों में भी प्रमुख स्थान रखता है। यह **रंगों का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक** है और वैश्विक **स्तर पर कृषि रसायनों का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक** है। इस क्षेत्र में लगभग 13,000 बड़े पैमाने की इकाइयां और 4.45 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं। कई पहल रासायनिक

विनिर्माण, अनुसंधान और औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रही हैं। इनमें समर्पित रासायनिक पार्क, वित्त पोषण के अवसर और गुणवत्ता और निवेश को बढ़ावा देने वाले उपाय शामिल हैं। साथ में, ये प्रयास वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को मजबूत करना चाहते हैं।

इंडिया केम 2026: उद्योग, निवेश और वैश्विक बाजार एक साथ

14वें इंडिया केम 2026 का आयोजन 22 से 24 अक्टूबर, 2026 तक मुंबई में किया गया था। तीन दिवसीय कार्यक्रम में रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इसकी थीम, "**एडवांटेज भारत: एक उभरता हुआ वैश्विक रसायन हब**", ने भारत की औद्योगिक क्षमताओं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अवसरों पर प्रकाश डाला। 5,000 से अधिक आगंतुकों के साथ, यह कार्यक्रम देश के मंचों, सीईओ फोरम और क्षेत्र-विशिष्ट गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से उद्योग जगत के दिग्गजों और व्यवसायों को एक साथ लाया। प्रदर्शनी में प्रौद्योगिकियों, उपकरणों और निवेश के अवसरों को प्रदर्शित किया गया, जबकि उद्घाटन इंडिया केम यूथ इनोवेशन चैलेंज ने छात्रों को व्यावहारिक, अनुसंधान-आधारित समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

विनिर्माण क्षमता और औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती

घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए निवेश, औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और एक सक्षम नीतिगत वातावरण की आवश्यकता होती है। भारत अधिकांश रासायनिक क्षेत्रों के लिए स्वतः मार्ग के माध्यम से शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देता है। स्वचालित मार्ग के तहत, भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश के लिए सरकार से पूर्व-अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। **2014-2026** के दौरान एफडीआई प्रवाह **1,04,895 करोड़ रुपये तक पहुंच गया**, जो 2004-2014 के दौरान दर्ज किए गए 45,240 करोड़ रुपये के दोगुने से भी अधिक है।

प्रमुख रसायनों और पेट्रोकेमिकल का उत्पादन 2015-16 में 45,638 हजार मीट्रिक टन (एमटी) से बढ़कर 2024-25 में **58,617 हजार मीट्रिक टन** हो गया। यह गति औद्योगिक क्षमता का विस्तार करने, विशेष विनिर्माण केंद्र विकसित करने और पूरे क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की पहल का पूरक है।



पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल में निवेश के क्षेत्र

पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन में निवेश के क्षेत्र (पीसीपीआईआर) की अवधारणा इस क्षेत्र को एकीकृत तरीके से बढ़ावा देना है। पीसीपीआईआर एक विशेष रूप से चित्रित निवेश क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल लगभग **250 वर्ग किमी है,** जिसमें लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए निर्धारित है। पीसीपीआईआर सामान्य इन्फ्रास्ट्रक्चर**,** आधारभूत उपयोगिताओं और सहायता सेवाओं के साथ क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण का पालन करते हैं। इनमें सड़कें, रेल नेटवर्क, बंदरगाह, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र, सीवेज निपटान संयंत्र, जल आपूर्ति और भाप उत्पादन इकाइयां शामिल हैं। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धी वातावरण प्रदान करता है।

- भारत में तीन पीसीपीआईआर हैं: गुजरात में दाहेज, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम-काकीनाडा और ओडिशा में पारादीप।
- इन क्षेत्रों में कुल मिलाकर 3.4 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ है।
- उन्होंने 3.7 लाख रोजगार पैदा किए हैं और 2,200 से अधिक रासायनिक विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की सुविधा प्रदान की है।

यह साझा औद्योगिक इकोसिस्टम आगे के निवेश और मूल्यवर्धन के लिए एक आधार प्रदान करता है।

भव्य रसायन: समर्पित केमिकल पार्क

जुलाई 2026 में स्वीकृत भारत औद्योगिक विकास योजना योजना (भव्य रसायन) योजना का उद्देश्य **तीन समर्पित केमिकल पार्क** स्थापित करना है। प्रत्येक पार्क कम से कम 8 वर्ग किलोमीटर (2,000 एकड़) भूमि को कवर करेगा। केंद्र प्रति पार्क 1,000 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान करेगा, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 500 करोड़ रुपये के योगदान के अधीन होगा। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय **3,030 करोड़ रुपये है**। इसमें से 3,000 करोड़ रुपये सामान्य इन्फ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि 30 करोड़ रुपये प्रशासनिक व्यय को कवर करते हैं। यह वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक पांच साल तक चलेगा।

ये पार्क रसायन उद्योग के लिए प्लग-एंड-प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएंगे, जिससे संसाधन के इस्तेमाल में सुधार और रसद लागत को कम करने में मदद मिलेगी। यह पर्यावरण के अनुकूल इकोसिस्टम के माध्यम से सतत औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देगा। इसमें सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र, भंडारण और निपटान सुविधाएं और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी केंद्रीकृत सुविधाएं शामिल हैं। इस योजना से निवेश आकर्षित करने, घरेलू उत्पादन क्षमता का विस्तार करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने की उम्मीद है।

प्लास्टिक पार्क: डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण को मजबूती

प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की योजना भारत के डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग का समर्थन करती है। यह घरेलू डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में पॉलिमर (एक पेट्रोकेमिकल) अवशोषण क्षमता और मूल्यवर्धन को बढ़ाने पर केंद्रित है। प्लास्टिक पार्क प्लास्टिक से संबंधित व्यवसायों और उद्योगों को समर्पित औद्योगिक क्षेत्र हैं। उनका उद्देश्य प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को मजबूत और समन्वित करना है। यह रोजगार पैदा करते हुए निवेश, उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देता है। इस योजना के तहत, सरकार परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान वित्त पोषण प्रदान करती है, जो प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन है। शेष परियोजना लागत राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों, लाभार्थी उद्योगों आदि द्वारा वित्त पोषित की जाती है।

ये पार्क अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण पहल के माध्यम से पर्यावरणीय रूप से सतत विकास को भी प्रोत्साहित करते हैं। यह उन्हें प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और रासायनिक उद्योग को मजबूत करने के भारत के प्रयासों

का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। **पूरे भारत में दस प्लास्टिक पार्कों** को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 4 ने **शत-प्रतिशत** इन्फ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम पूरा कर लिया है, जिनमें से तीन 2025-26 के दौरान पूरे हुए हैं।



अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास

जैसे-जैसे उद्योगों में रासायनिक अनुप्रयोगों का विस्तार हो रहा है, विशेष ज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। कई पहल क्षेत्र-विशिष्ट अनुसंधान, विशेष तकनीकी शिक्षा और उद्योग-उन्मुख कौशल विकास के माध्यम से इन प्रयासों को आगे बढ़ा रही हैं।

रासायनिक संवर्धन और विकास योजना

रासायनिक संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस) ज्ञान निर्माण, प्रसार और अनुसंधान संवर्धन के माध्यम से रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग के विकास की सुविधा प्रदान करती है। यह क्षेत्र-विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न करने के लिए अध्ययन, सर्वेक्षण, डेटाबेस और प्रचार सामग्री का समर्थन करता है। यह योजना इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देकर अनुसंधान और नवाचार को भी प्रोत्साहित करती है। यह कार्यशालाओं, सेमिनारों,

अध्ययनों और संबंधित गतिविधियों के लिए संगठनों, उद्योग संघों और अन्य संस्थाओं को अनुदान सहायता (सामान्य) प्रदान करता है।

- 2016 से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड ने सीपीडीएस के तहत किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
- कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) ने भी 2022-23 से इन कार्यक्रमों का संचालन शुरू किया। वे कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देते हैं और एकीकृत कीट प्रबंधन प्रणालियों को प्रोत्साहित करते हैं।
- इन प्रणालियों का उद्देश्य खाद्यान्नों, खाद्य तेलों, फलों और सब्जियों में कीटनाशक अवशेषों को कम करना है। अगस्त 2026 तक **250 से अधिक कार्यक्रमों** से देश भर में **1 लाख से अधिक किसानों** को लाभ हुआ है।

अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना

नवंबर 2025 में शुरू की गई, अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना में अनुसंधान और नवाचार में निजी क्षेत्र के निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए **1 लाख करोड़ रुपये** का कोष है। यह परिवर्तनकारी परियोजनाओं के लिए अनुकूल शर्तों पर दीर्घकालिक वित्तपोषण और पुनर्वित्त प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने में तेजी लाना, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना और महत्वपूर्ण और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

8 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी, उन्नत रसायन, पेट्रोकेमिकल और सामग्री प्रौद्योगिकी योजना के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र एक अतिरिक्त प्रौद्योगिकी क्षेत्र बन गया है। यह समावेशन क्षेत्रीय अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करेगा और उन्नत औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास की सुविधा प्रदान करेगा।

सीआईपीईटी: तकनीकी शिक्षा, कौशल और उद्योग सहायता

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी-सिपेट) एक केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थान है। यह भारत के पेट्रोकेमिकल और संबद्ध उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता, शैक्षणिक और अनुसंधान (स्टार) गतिविधियों का संचालन करता है। सिपेट ने कई केंद्रों और प्रयोगशालाओं के माध्यम से विस्तार किया है। इनमें सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट (सीएसटीएस), प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर (पीडब्लूएमसी) और स्कूल ऑफ एडवांस रिसर्च इन

पेट्रोकेमिकल्स (एसएआरपी) शामिल हैं। अन्य सुविधाओं में एडवांस रिसर्च स्कूल फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट सिमुलेशन (एआरएसटीपीएस) और एडवांस पॉलिमर डिजाइन एंड डेवलपमेंट रिसर्च लेबोरेटरी (एपीडीडीआरएल) शामिल हैं।

- सिपेट के नेटवर्क में अब **51 केंद्र** शामिल हैं, जिनमें 2014 से स्थापित **19 केंद्र** शामिल हैं। इनमें से तीन केंद्र प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समर्पित हैं।
- संस्थान ने लगभग **6.72 लाख** कुशल पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है, जिसमें 2014-24 के दौरान 5.21 लाख से अधिक शामिल हैं। इसने इसी अवधि के दौरान **8.53 लाख** प्रौद्योगिकी सहायता सेवा कार्य भी पूरे किए।

उत्कृष्टता केंद्र

मौजूदा प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने, अनुसंधान को मजबूत करने और नए अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। **18 केंद्रों** ने **85 पेटेंट** दायर किए हैं, **600 से अधिक रिसर्च पेपर** प्रकाशित किए हैं और **105 नई प्रौद्योगिकियों** और उत्पादों को विकसित किया है। ये उपलब्धियां स्वदेशी क्षमताओं के निर्माण और औद्योगिक नवाचार का समर्थन करने में अनुसंधान संस्थानों की भूमिका को प्रदर्शित करती हैं।

रसायनों का गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग

रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में जिम्मेदार विकास के लिए गुणवत्ता मानक और कार्यस्थल की सुरक्षा अनिवार्य है। नियामक उपाय उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, जबकि लक्षित प्रशिक्षण औद्योगिक श्रमिकों को खतरनाक रसायनों को सुरक्षित रूप से संभालने में सक्षम बनाता है।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश

उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण को बढ़ावा देने और घटिया आयात पर अंकुश लगाने के लिए, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी किए गए हैं। अगस्त 2026 तक, **37 क्यूसीओ** लागू हैं, जिससे निर्दिष्ट रासायनिक और पेट्रोकेमिकल मानक अनिवार्य हो गए हैं। इन आदेशों के लिए घरेलू निर्माताओं और आयातकों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है।

कार्यस्थल की सुरक्षा और खतरनाक रासायनिक प्रबंधन

बड़ी दुर्घटनाओं वाली खतरनाक (एमएएच) औद्योगिक इकाइयों के कार्यबल के लिए विकसित भारत@2047 कार्य योजना के तहत एक राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह "कार्यस्थल पर खतरनाक रसायनों के सुरक्षित संचालन और खतरनाक रसायनों से जुड़े जोखिम में कमी के प्रयास" पर केंद्रित है। कार्यक्रम को 5 वर्षों में सभी 2,393 एमएएच इकाइयों को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 एमएएच इकाइयों के 100 प्रतिभागियों को शामिल किया जाता है, जिसमें प्रत्येक इकाई से दो कर्मचारी भाग लेते हैं।

अगस्त 2026 तक, देश भर में **21 प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किए जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में 1,376 औद्योगिक इकाइयों ने भाग लिया और **2,441 कर्मियों** को प्रशिक्षित किया। यह पहल कार्यस्थल की तैयारियों को मजबूत करने और खतरनाक रासायनिक प्रबंधन के बारे में जागरूकता में सुधार करने का प्रयास करती है।

एकीकृत और प्रतिस्पर्धी उद्योग की ओर

भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग विनिर्माण गतिविधियों, औद्योगिक अनुप्रयोगों और डाउनस्ट्रीम उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला तक फैला हुआ है। इसके विकास में उत्पादन क्षमता का विस्तार करना, विशेष औद्योगिक सुविधाओं की स्थापना करना और निवेश के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना शामिल है। विनिर्माण के साथ-साथ, अनुसंधान संबंधी पहल और तकनीकी संस्थान ज्ञान विकास, प्रौद्योगिकी उन्नति और कार्यबल प्रशिक्षण में योगदान करते हैं। गुणवत्ता मानक और खतरनाक रासायनिक प्रबंधन उत्पाद अनुपालन और कार्यस्थल सुरक्षा का समाधान करते हैं। इंडिया केम 2026 ने इन घरेलू विकासों को अंतरराष्ट्रीय भागीदारी, उद्योग जुड़ाव और सहयोग के अवसरों से जोड़ा। साथ में, ये क्षेत्र क्षेत्र के औद्योगिक विकास और वैश्विक जुड़ाव को आकार देने वाले प्रयासों की व्यापकता को दर्शाते हैं।

संदर्भ

रसायन और उर्वरक मंत्रालय: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

https://chemicals.gov.in/

https://chemicals.gov.in/sites/default/files/Reports/annual_report_2025-26_Eng_1.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2246357&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2325901&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2294832&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2323590&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2120876&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2220980&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2288866&lang=1&reg=48

https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2327972&reg=48&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2326667&reg=6&lang=1

पीआईबी शोध

***

पीके/केसी/आरटी/एसकेएस/एचबी